*फिनटेक और बदलते वित्तीय परिदृश्य**

शक्तिकान्त दास

वैश्विक फिनटेक महोत्सव (जीएफएफ) के चौथे संस्करण में यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं समावेशी, समुत्थानशील और शाश्वत वित्तीय प्रणाली के एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस तीन दिवसीय आयोजन के लिए फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। यह कहना उचित होगा कि नवाचार फिनटेक उद्योग का आधार है। ऐसे आयोजन घरेलू और वैश्विक दोनों सहभागियों के साथ ज्ञान और अनुभव साझा करने में सक्षम होते हैं, जो अधिक नवाचार की सुविधा प्रदान करते हैं। विनियामकों और फिनटेक सहभागियों को एक ही मंच पर लाकर, यह महोत्सव एक तरफ उद्योग द्वारा विनियामकीय अपेक्षाओं की समझ की सुविधा प्रदान करता है, और दूसरी ओर उद्योग के विकास और विनियामकों द्वारा अपेक्षाओं की जानकारी प्रदान करता है। इस तरह के विषयगत कार्यक्रम एक अधिक जीवंत फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण के लिए सही प्रकार का मंच प्रदान करते हैं।

आज अपने संबोधन में, मैं फिनटेक के आगमन के साथ वित्तीय परिदृश्य में आए परिवर्तनों पर चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की भूमिका और नवाचार को बढ़ावा देने में रिज़र्व बैंक की भूमिका पर बल होगा।

फिनटेक के आगमन के साथ पारंपरिक वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। इस परिवर्तन ने वित्तीय सेवाओं को तेज, सस्ता, कुशल और अधिक सुलभ बनाकर उनकी लोगों तक पहुंच को काफी प्रभावित किया है। वैश्विक फिनटेक क्षेत्र, जो वर्तमान में 245 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है – जो वैश्विक वित्तीय सेवाओं के राजस्व का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा है - 2030 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व तक पहुंचने का अनुमान है[1]। भारतीय फिनटेक उद्योग में वर्ष 2030 तक लगभग 200 बिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है[2]। यह अनुमान इंगित करता है कि 2030 तक, भारत का फिनटेक क्षेत्र संभावित रूप से वैश्विक फिनटेक उद्योग के कुल राजस्व में लगभग 13 प्रतिशत का योगदान दे सकता है। ये अनुमान भारतीय फिनटेक क्षेत्र के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हैं।

फिनटेक द्वारा प्रौद्योगिकीय नवाचार अंतर्निहित तीन तत्वों - (i) डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे; (ii) संस्थागत व्यवस्था; और (iii) नीतिगत पहल के बीच परस्पर सामंजस्य का परिणाम हैं। ये प्रमुख तत्व रचनात्मक विचारों को पोषित करने और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं, जिससे वित्तीय उद्योग में लाभकारी और प्रभावशाली परिवर्तन होते हैं। मैं इन तीन पहलुओं के बारे में विस्तार से बात करना चाहूंगा।

क. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को आमतौर पर एक प्रौद्योगिकी प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक और निजी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में परस्पर परिचालनीयता, खुलेपन और समावेश को बढ़ावा देती है। डिजिटलीकरण के भारतीय 'मॉडल' की यह उल्लेखनीय विशेषता है कि यह सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा एक बुनियादी ढांचे के निर्माण में की गई पहल है, जिसके आधार पर निजी क्षेत्र की फिनटेक फर्मों और स्टार्ट-अप द्वारा अभिनव उत्पाद बनाए गए हैं। वास्तव में, भारत ने *इंडिया स्टैक* की अवधारणा के साथ डीपीआई के लिए परतदार दृष्टिकोण की दिशा में पहल की है। इस संबंध में, वित्तीय समावेशन, वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के उद्भव के संदर्भ में जेएएम ट्रिनिटी, अर्थात जन धन योजना, आधार और मोबाइल का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है।

(i) जन धन योजना/बैंक खाते

विश्व बैंक के ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2021 के अनुसार, दुनिया भर में 76 प्रतिशत वयस्कों के पास बैंक या विनियमित वित्तीय संस्थान में खाता है, जबकि 2011 में यह आंकड़ा 51

---

* ग्लोबल फिनटेक महोत्सव, मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का मुख्य भाषण- 6 सितंबर, 2023।

[1] https://www.bcg.com/publications/2023/future-of-fintech-and-banking

[2] https://www.ey.com/en_in/financial-services/how-is-the-fintech-sector-in-india-poised-for-exponential-growth

प्रतिशत था। इसकी तुलना में, भारत में बैंक खाते तक पहुंच रखने वाले वयस्कों का प्रतिशत 2011 में 35 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 78 प्रतिशत हो गया। जैसा कि आप जानते होंगे, बैंक खाते के सार्वजनीकरण के लिए 2014 में सरकार द्वारा शुरू की गई जन धन योजना ने इस उल्लेखनीय प्रगति को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक, भारत में 500 मिलियन से अधिक जन धन बैंक खाते खोले गए हैं[3]।

(ii) *आधार*- डिजिटल पहचान

आधार, भारत की बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है जो पहचान का एकल और पोर्टेबल प्रमाण प्रदान करती है। 30 नवंबर 2022 तक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 1.35 बिलियन *आधार* पहचान जारी किए[4]। विशिष्ट *आधार* पहचान संख्या व्यक्तियों को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करने की सुविधा देती है, भले ही उनका स्थान कुछ भी हो, जिससे वित्तीय सेवाओं, लक्षित वित्तीय सब्सिडी, लाभ और राष्ट्रव्यापी अन्य सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होती है। इसने फिनटेक को कागज रहित और संपर्क रहित वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने में भी सक्षम बनाया है। *आधार* ने ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाया है, वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा को मजबूत किया है और पहचान संबंधी धोखाधड़ी के जोखिम को काफी हद तक कम कर दिया है। सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने का यह एक अच्छा उदाहरण है।

(iii) मोबाइल कनेक्टिविटी

मोबाइल कनेक्टिविटी के प्रसार ने भारत में वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत में मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014[5] में लगभग 70 मिलियन थी जो बढ़कर 2022[6] में लगभग 800 मिलियन हो गई। इसी अवधि के दौरान, भारत में डिजिटल लेनदेन की संख्या जो 2014[7] में लगभग 1.2 बिलियन थी, बढ़कर 2022[8] में लगभग 91 बिलियन हो गई। मोबाइल फोन ले सकने के सामर्थ्य, डेटा तक सस्ती पहुंच और मोबाइल नेटवर्क कवरेज के विस्तार ने मोबाइल वॉलेट, यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान विधियों को अपनाने में वृद्धि को प्रेरित किया है।

(iv) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)

यूपीआई ने भारत में फिनटेक क्रांति में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। इसकी सफलता की कहानी वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बन गई है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच तुरंत धन अंतरित करने की इसकी क्षमता ने लोगों को डिजिटल लेनदेन करने के तरीके को बदल दिया है। बैंकों में यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी ने एक एकीकृत भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। इसके उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और क्यूआर कोड-आधारित भुगतान ने इसे बहुत लोकप्रिय बना दिया है। इसने छोटे व्यवसायों और सड़क विक्रेताओं के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की है, जिससे अधिक वित्तीय समावेशन हुआ है।

यूपीआई ने फिनटेक क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा दिया है, जिससे अन्य भुगतान प्रणालियों की वृद्धि और विकास हुआ है। उदाहरण के लिए, यूपीआई-आधारित प्लेटफार्मों द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रदान करना शुरू करने के बाद भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से लेनदेन की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स/मोबाइल वॉलेट की संख्या भी बढ़ी है जब मोबाइल वॉलेट को यूपीआई के जरिए इंटरऑपरेबल बनाया गया था। यूपीआई की सफलता सरासर संख्या में परिलक्षित होती है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम समय में बढ़ी है। अगस्त 2023 में ₹ 15 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के 10 बिलियन से अधिक लेनदेन किए गए । यह संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत के प्रौद्योगिकी स्टैक ने मोबाइल फोन और इंटरनेट; पहचान प्रणाली; डेटा शेयरिंग रेल (एए फ्रेमवर्क[11]); पेमेंट रेल; और बैंक खातों के सार्वजनीकरण के माध्यम से डिजिटलीकरण को गति दी है।

---

3 https://pmjdy.gov.in/

4 https://uidai.gov.in/en/about-uidai/

5 https://www.trai.gov.in/release-publication/reports/telecom-subscriptions-reports

6 https://www.trai.gov.in/release-publication/reports/telecom-subscriptions-reports

7 https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=184668

8 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1897272

9 https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/product-statistics

10 बीआईएस आलेख क्र. 106, डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का डिजाइन: भारत से सबक, दिसंबर 2019।

11 एकाउंट एग्रीगेटर (एए) ढांचा वित्तीय संस्थानों में उपयोगकर्ताओं द्वारा डेटा के सुरक्षित और सहमति-आधारित साझाकरण को सक्षम बनाता है।

ख. संस्थागत व्यवस्था

वित्तीय प्रणाली के विकास के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। वे अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी समाधानों को आगे बढ़ाने और वित्त में सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने जैसे विभिन्न कार्य करती हैं। वे वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रथाओं को भी बढ़ावा देती हैं। फिनटेक क्षेत्र के लिए संस्था निर्माण में रिज़र्व बैंक की पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी)[12] की स्थापना जो भारतीय बैंकिंग उद्योग के डिजिटल परिवर्तन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है; (ii) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड (एनपीसीआई)[13] का सृजन, जो भारत में खुदरा डिजिटल भुगतानों के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभरा है; (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा यथा अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यक सेवाएं डिजाइन करने, तैनात करने और प्रदान करने के लिए भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस)[14] नामक संस्था की स्थापना; (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग क्षेत्र की साइबर समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2016 में रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी)[15] की स्थापना; (v) 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक में फिनटेक विभाग का गठन; (vi) वित्तीय सेवाओं में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना।

ग. नीतिगत पहल

फिनटेक क्षेत्र के विकास को आकार देने में समय पर और उचित नीतिगत पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी नीतिगत पहलों का लक्ष्य नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना और वित्तीय सेवाओं की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। हमने हाल के दिनों में इस तरह की कई नीतिगत पहल की हैं। इनमें भुगतान बैंक (2014), एकाउंट एग्रीगेटर (एए) [2016], प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (2017), पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) ऋण (2017), इनवॉयस डिस्काउंटिंग (व्यापार प्राप्य और छूट प्रणाली - टीआरईडीएस) [2018], और डिजिटल उधार दिशानिर्देश (2022, 2023) जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए विनियामकीय दिशानिर्देश जारी करना शामिल है। उल्लेखनीय है कि एकाउंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से सहमति-आधारित जानकारी साझा करने की संचयी संख्या जुलाई 2023 में 15.65 मिलियन तक पहुंच गई है। बीमा, पूंजी बाजार और पेंशन फंड की इकाइयों के एए ढांचे में शामिल होने के साथ इसे बहुत अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है।

विनियामकीय सैंडबॉक्स ढांचे की घोषणा अगस्त 2019 में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवाओं में दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। खुदरा भुगतान, सीमा पार भुगतान, एमएसएमई ऋण और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम पर चार कोहोर्ट, तटस्थ पांचवें कोहोर्ट के साथ, फिनटेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। विनियामकीय सैंडबॉक्स के पहले कोहोर्ट से मिली सीख के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 'ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए एक रूपरेखा' तैयार की है, जो खराब या कमजोर इंटरनेट या कमजोर दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक अब नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हैकाथॉन आयोजित कर रहा है। हमारा पहला हैकाथॉन, हारबिंगर 2021 में आयोजित किया गया था जिसका व्यापक विषय था - 'स्मार्ट डिजिटल भुगतान'। हमारे वैश्विक हैकाथॉन का दूसरा संस्करण - 'हारबिंगर 2023' भी 'समावेशी डिजिटल सेवाओं' विषय के साथ शुरू किया गया है।

---

[12] 1996 में स्थापित आईडीआरबीटी, सुरक्षित और कुशल बैंकिंग प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा समाधान और नीति ढांचे विकसित करता है। इसने राष्ट्रीय वित्तीय स्विच, एसएफएमएस और इनफाइनेट भी बनाया।

[13] एनपीसीआई की स्थापना 2008 में रिज़र्व बैंक की पहल पर की गई थी। एनपीसीआई के यूपीआई, आईएमपीएस, रुपे कार्ड और बीबीपीएस, एनएसीएच और एईपीएस जैसे अन्य डिजिटल नवाचारों ने भारत में भुगतान प्रणाली को बदल दिया है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) उपयोगकर्ताओं को विभिन्न उपयोगिता बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाती है; नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) थोक और दोहराए जाने वाले लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है; और आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लोगों को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके बुनियादी बैंकिंग लेनदेन करने की सुविधा देती है।

[14] आईएफटीएएस भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इनफाइनेट) और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) सेवाओं को 24 * 7 * 365 संचालित करता है। ये दोनों सेवाएं भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती हैं। वे एनईएफटी और आरटीजीएस भुगतान लेनदेन को भी सक्षम करते हैं। आईएफटीएएस कई बैंकों के लिए मोबाइल वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग जैसे क्लाउड-आधारित समाधान भी प्रदान करता है।

[15] आरईबीआईटी भारतीय रिज़र्व बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं के साइबर सुरक्षा मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करता है।

घ. वर्तमान पहल

अब मैं रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में की गई कुछ प्रौद्योगिकी आधारित पहलों की ओर मुड़ता हूं जो निश्चित रूप से परिवर्तनकारी हैं।

(i) केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

सीबीडीसी कई अद्वितीय अवसर प्रदान करता है क्योंकि यह भुगतान प्रणाली के विकास में अगले मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आप जानते होंगे, रिज़र्व बैंक ने थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए भारत के सीबीडीसी (ई-रुपी) का पायलट रन शुरू किया है। सीबीडीसी-थोक पायलट को 1 नवंबर 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन को निपटाने के लिए शुरू किया गया था। हम आगे चलकर कुछ और उपयोग के मामलों का परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं।

सीबीडीसी-खुदरा पायलट को 1 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया था और इसमें पर्सन टू पर्सन (पी2पी) और पर्सन टू मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन, दोनों शामिल हैं। पायलट में डिजिटल रुपया निर्माण, वितरण और वास्तविक समय में खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण किया जा रहा है। यह पायलट वर्तमान में 26 शहरों में 13 बैंकों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। लगभग 1.46 मिलियन उपयोगकर्ता और 0.31 मिलियन व्यापारी वर्तमान में 31 अगस्त 2023 तक इस पायलट का हिस्सा हैं।

कहने की जरूरत नहीं है, अगली पीढ़ी की मुद्रा प्रणाली के रूप में, सीबीडीसी को एक अविघटनकारी तरीके से पेश करने की आवश्यकता है। इसलिए, हम नपा-तुला और चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति का अनुसरण कर रहे हैं। हाल ही में हमने यूपीआई क्यूआर कोड के साथ सीबीडीसी की पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम किया है और दिसंबर 2023 तक प्रति दिन एक मिलियन सीबीडीसी लेनदेन का लक्ष्य रखा है। यह हमें विभिन्न डिजाइन विकल्पों, उपयोग के मामलों और व्यवहार पैटर्न का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सूचना बिंदु उपलबब्ध कराएगा।

(ii) बाधा रहित ऋण के लिए पब्लिक टेक प्लैटफॉर्म

सितंबर 2022 में पिछले जीएफएफ में, मैंने कुछ राज्यों में छोटे कृषि ऋणों (किसान क्रेडिट कार्ड - केसीसी ऋण के रूप में जाना जाता है) के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण पर पायलट शुरू करने और ऋणों के सभी क्षेत्रों के लिए बाधा रहित ऋण उपलबध करने के लिए एक मंच विकसित करने के हमारे प्रयास के बारे में उल्लेख किया था।

केसीसी डिजिटलीकरण पर पायलट परियोजना सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के चुनिंदा जिलों में शुरू की गई थी। पायलट परियोजना के तहत डिजिटाइज्ड स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स डेटाबेस, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज (सीआईसी), सैटेलाइट डेटा, आधार ई-केवाईसी आदि के साथ एकीकृत करके किसानों को कुछ ही मिनटों में प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपये (किसी भी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं) तक के कृषि ऋण का सफल वितरण किया गया। किसान नए केसीसी ऋण तथा केसीसी ऋण नवीकरण के लिए सीधे अपने स्थान से या कहीं से भी स्मार्टफ़ोन / टैबलेट पर सीधे या सहायता प्राप्त मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केसीसी पायलट परियोजना को बाद में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनिंदा जिलों में विस्तारित किया गया है। कुल सात बैंक अब डिजिटल केसीसी पायलट का हिस्सा हैं। पायलट परियोजना का विस्तार गुजरात के डेयरी किसानों के लिए भी किया गया है। ऐसे डेयरी ऋणों के लिए वित्त की पात्रता और पैमाना दुग्ध सहकारी समितियों के पास उपलब्ध दूध संग्रह आंकड़ों के आधार पर तुरंत तय किया जाता है।

हम अब डिजिटल केसीसी ऋण से आगे की बात करेंगे जो मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। वर्तमान में, क्रेडिट मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा केंद्र और राज्य सरकारों, प्रौद्योगिकी और फिनटेक कंपनियों, बैंकों, सेवा प्रदाताओं जैसे क्रेडिट सूचना कंपनियों, डिजिटल पहचान प्राधिकरणों आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं की अलग-अलग प्रणालियों में मौजूद है। विभिन्न डेटा स्रोतों के पास उपलब्ध ग्राहक डेटा तक पहुंचना बैंकों के लिए एक चुनौती है क्योंकि इसके लिए प्रत्येक सूचना प्रदाता के साथ एकीकरण की आवश्यकता होगी। यह उधारकर्ता के लिए भी एक चुनौती है। बाधा रहित ऋण को मूर्त रूप देने के लिए अगस्त 2023 में रिज़र्व बैंक ने एक डिजिटल पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की, जिसकी अवधारणा और विकसित करने का कार्य आरबीआईएच के सहयोग से किया गया है। यह प्लैटफार्म उक्त सभी स्रोतों से उधारदाताओं को डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाता है, जिससे कई एकीकरणों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

इस प्लैटफॉर्म पर पायलट प्रोजेक्ट 17 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। शुरुआत में यह प्लैटफॉर्म एमएसएमई ऋण

(संपार्श्विक के बिना), व्यक्तिगत ऋण और आवास ऋण जैसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अनुभव के आधार पर, पायलट परियोजना के दौरान अधिक उत्पादों, सूचना प्रदाताओं और उधारदाताओं को शामिल करने के लिए इसके दायरे और व्याप्ति क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

ई. ग्राहक केंद्रितता, अभिशासन और स्व-विनियमन

अब मैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात करना चाहूंगा जो फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिर और भविष्य के लिए तैयार होने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, तीन महत्वपूर्ण मुद्दे, अर्थात् ग्राहक केंद्रितता, अभिशासन, और स्व-विनियमन ध्यान देने योग्य हैं। व्यवसाय की गतिशील और लगातार विकसित होती दुनिया में, राजस्व, निवल आय और मूल्यांकन के लिए अथक प्रयासों की खोज में जकड़ जाना स्वाभाविक है। कभी-कभी, यह भुला दिया जाता है कि किसी भी उद्यम की सफलता उसके अपने ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी होती है। यह पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं उजागर करना चाहता हूं। हमें याद रखना चाहिए कि स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, "आपको ग्राहक अनुभव से शुरू करना होगा और प्रौद्योगिकी के लिए विपरीत दिशा से काम करना होगा"[16]।

ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है ग्राहकों की जरूरतों को समझकर नवाचार के लिए ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना, ऐसे प्रावधान करना जो ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हैं और उनका विश्वास अर्जित करते हैं। यह एक संगठनात्मक संस्कृति विकसित करने की मांग करता है जिसमें व्यावसायिक रणनीति में निरंतर प्रतिसूचना तंत्र अंतर्निहित है। ग्राहकों की जरूरतों को सुरक्षित और कुशलता से पूरा करने वाले समाधानों को डिजाइन करना न केवल ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करेगा, बल्कि यह एक स्थायी तरीके से व्यावसायिक उद्देश्यों को भी पूरा करेगा। यह सरलीकृत उपयोगकर्ता इंटरफेस और त्वरित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दीर्घकालिक ग्राहक विश्वास प्राप्त करने के लिए ग्राहक उत्पीड़न को दूर करना आवश्यक है।

इस संदर्भ में, मैं आगे जोड़ना चाहूंगा कि डिजिटल नवाचारों ने कई बार साइबर-जोखिम और डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को भी जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, अवैध ऋण एप्प, जिनमें से कई विदेशों में बने थे, ने डेटा गोपनीयता के उल्लंघन, अनैतिक व्यावसायिक आचरण, अत्यधिक ब्याज दरों की वसूली और कठोरतापूर्वक वसूली प्रथाओं की गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है। इससे यह बात ध्यान में आती है कि नवाचारों को विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों और जिम्मेदार आचरण के साथ तुरंत जोड़ने की आवश्यकता है। यह भी अत्यावश्यक है कि विनियमित संस्थाएं लाइसेंसिंग शर्तों द्वारा निर्धारित परिधि के भीतर काम करें और केवल उन गतिविधियों को करें जिन्हें विनियमों के तहत अनुमति दी गई है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है - फिनटेक में अभिशासन की महत्वपूर्ण भूमिका। स्पष्ट अभिशासन संरचना मुहैया कराके फिनटेक कंपनियां पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदार निर्णय लेने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकती हैं। वास्तव में, फिनटेक में प्रभावी अभिशासन के लिए विनियामकों, उद्योग संघों और फिनटेक समुदाय को शामिल करते हुए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। विनियामक मध्यस्थता संबंधी कार्य करने, मौजूदा कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिए विनियमों को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योग संघ सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिनटेक को खुद निभानी होगी। उन्हें सक्रिय रूप से अभिशासन के उच्च मानकों को अपनाना चाहिए। एक मजबूत अभिशासन संरचना में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, जवाबदेही तंत्र और हितधारकों की भागीदारी का स्पष्ट चित्रण शामिल है। सुशासन को प्रभावी निगरानी, नैतिक आचरण और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः, यह सुशासन ही है जो फिनटेक की टिकाऊ और दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं वह है फिनटेक सहभागियों द्वारा एक प्रभावी स्व-विनियामकीय संरचना स्थापित करने की आवश्यकता। उन्हें चाहिए कि वे देश के कानूनों के अनुरूप उद्योगजगत की सर्वोत्तम प्रथाओं, गोपनीयता और डेटा संरक्षण मानदंडों को विकसित करने के लिए कार्य करें, गलत बिक्री से बचने के लिए मानक निर्धारित करें, नैतिकतायुक्त व्यापार प्रथाओं, मूल्य निर्धारण, आदि में पारदर्शिता को बढ़ावा दें। मैं इस अवसर पर आग्रह करता हूं और इस बात को

[16] वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फरेन्स, 1997 (स्टीव जॉब्स)।

प्रोत्साहित करता हूं कि फिनटेक सहभागी स्वयं एक स्व-विनियामकीय संगठन (एसआरओ) स्थापित करने की पहल करें।

संक्षेप में

प्रौद्योगिकीय नवाचार में वित्त को अधिक समावेशी, प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाने की अभूतपूर्व क्षमता है। यह महत्वपूर्ण है कि फिनटेक की दुनिया में प्रौद्योगिकीय प्रगति एक जिम्मेदार तरीके से विकसित हो और वास्तव में बड़े पैमाने पर लोगों के लिए फायदेमंद हो। इसलिए, इन नवाचारों का विस्तार होना और इंटरऑपरेबल होना महत्वपूर्ण है। फिनटेक सहभागियों को खुद जिम्मेदार डिजिटल नवाचारों को सुनिश्चित करना चाहिए। रिज़र्व बैंक अपनी ओर से एक सक्रिय और उत्तरदायी फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विनियामकीय और अन्य नीतिगत उपायों पर कार्य करना जारी रखेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही वित्तीय सेवाओं की मांग बढ़ रही है। आने वाले वर्ष बहुत सारी संभावनाओं से भरे हुए हैं। इसलिए दुनिया भर के नवप्रवर्तकों को इन अवसरों का लाभ उठाने पर विचार करना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह वैश्विक फिनटेक महोत्व भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी क्षमता को उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में उभरेगा।

इस वैश्विक फिनटेक महोत्व की सफलता के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।